ASIA LOW CARBON BUILDINGS TRANSITION PROJECT
Life Cycle Assessment for Transitioning to a Low-Carbon Economy | PROJECT

एशिया लो-कार्बन बिल्डिंग परिवर्तन (ALCBT) परियोजना

हरियाणा | भारत

परियोजना स्थान	एशिया / भारत
परियोजना अवधि	अगस्त 2023 – अगस्त 2028
परियोजना वित्तपोषण	यूरो 1.93 करोड़ (भारत – यूरो 0.46 करोड़)
विषय	हरित निवेश, जलवायु कार्रवाई, हरित भवन, नीति
GGGI परियोजना कोड	ROA035

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

भारत में विविध जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण भवनों में ऊर्जा उपयोग के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। भवन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त बनाने के भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप, एशिया लो-कार्बन बिल्डिंग परिवर्तन (Asia Low Carbon Buildings Transition – ALCBT) परियोजना भवनों में निहित और परिचालन कार्बन का आकलन करेगी। साथ ही, यह परियोजना ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Building Code – ECBC) को व्यापक रूप से लागू करने में सहायता करेगी। हरियाणा में कम-कार्बन भवनों की पहचान के लिए 600 भवनों का एक विस्तृत भवन अभिलेख (सूची) तैयार किया गया है। इनमें से 22 चयनित भवनों को ऊर्जा-कुशल और प्राकृतिक शीतलन उपायों के साथ उन्नत किया गया है।

यह परियोजना भारत में 4,950 से अधिक सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों, भवन विशेषज्ञों, ऊर्जा लेखा परीक्षकों, ऊर्जा सेवा कंपनियों (Energy Service Companies – ESCOs), बैंकों और वित्तीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करेगी। साथ ही, यह भारत में कम-कार्बन परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए वित्त जुटाने में भी सहायता करेगी।

परियोजना का लक्ष्य और उद्देश्य

इस परियोजना का लक्ष्य देशभर में लो-कार्बन भवनों (Low Carbon Buildings – LCBs) की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देना है। यह लक्ष्य तकनीकी, नीतिगत और संस्थागत उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी होगी।

यह परियोजना भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA) के मार्गदर्शन में केरल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।

संघ भागीदार

प्रमुख

राज्य सरकार के भागीदार

वित्तीय सहयोगी

Supported by: Federal Ministry for the Environment, Climate Action, Nature Conservation and Nuclear Safety based on a decision of the German Bundestag | IKI International Climate Initiative

समन्वयक मंत्रालय

Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

© GGGI2026. उत्तर हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड।

हरियाणा अध्याय

भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण शीतलन की बढ़ती आवश्यकता है। अनुमान है कि 2030 तक भवन क्षेत्र लगभग **85,000** करोड़ किलोवाट-घंटे (kWh) बिजली की खपत करेगा।

2030 तक भारत के भवन अवसंरचना का लगभग 70% हिस्सा अभी निर्मित होना बाकी है, जो कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार का इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (India Cooling Action Plan – ICAP) शीतलन की मांग को कम करने और ऊर्जा-कुशल भवनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

हरियाणा, जो देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक राज्यों में से एक है, अत्यधिक तापमान का अनुभव करता है—गर्मियों में 45°C तक और सर्दियों में काफी ठंड। यह तापमान अंतर भवनों में ऊर्जा मांग को काफी बढ़ाता है।

ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (Global Green Growth Institute – GGGI), भारत-जर्मन द्विपक्षीय समझौते के तहत, भारत के तीन राज्यों में ALCBT परियोजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited – EESL) और हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (Haryana Renewable Energy Development Agency – HAREDA) के साथ मिलकर इस परियोजना को हरियाणा में कार्यान्वित किया जा रहा है।

भवन अभिलेख (Building Registry)

परियोजना के तहत 1,600 नए और मौजूदा भवनों का एक विस्तृत अभिलेख तैयार किया गया है, जिसमें से हरियाणा के 600 भवनों का गहन विश्लेषण किया गया है।

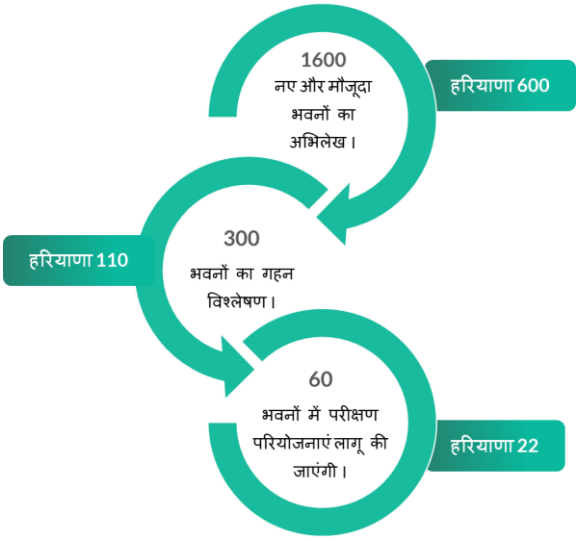

भारत और हरियाणा के भवन अभिलेख

Learn more at www.alcbt.gggi.org

#AsiaLowCarbonBuildings
#IndiaTowardsLCBT
#LowCarbonHighComfort

हरियाणा में परियोजना के अपेक्षित परिणाम

2028 तक, भारत में प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा 'लो कार्बन बिल्डिंग' (LCB) के लिए तकनीकी, नियोजन और संस्थागत उपकरण विकसित और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जाएंगे।

- **2.7** लाख टन उत्सर्जन में कमी
- **8** सार्वजनिक और निजी संस्थान LCBs से संबंधित उपकरण और प्रशिक्षण अपनाएंगे
- **~1** नीतिगत सिफारिश अपनाई जाएगी
- **~ 2.2** करोड़ निवेश जुटाया जाएगा
- **22** भवनों में परीक्षण परियोजनाएं लागू की जाएंगी (प्राकृतिक शीतलन तकनीकों के साथ)

30 अक्टूबर 2025 को राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं ALCBT परियोजना प्रसार कार्यशाला के दौरान "डीप-डाइव एवं कार्बन प्रदर्शन विश्लेषण" रिपोर्ट का विमोचन।

तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की बैठक: नई दिल्ली, भारत, 30 जुलाई, 2024।

GGGI भारत
एम-6, तीसरी मंजिल, अरविंदो मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली 110016, भारत
ईमेल: india@gggi.org

GGGI मुख्यालय
19वीं मंजिल, जियोंगडॉन्ग बिल्डिंग, 21-15 जियोंगडॉन्ग-गिल, जुंग-गु, सियोल, कोरिया गणराज्य 04518
ईमेल: communications@gggi.org

www.gggi.org
हमारी गतिविधियों से जुड़ें: